एलपीजी किल्लत खत्म बुकिंग में रफ्तार

पैनिक बुकिंग घटी, कंपनियां मांग से ज्यादा डिलीवरी कर रहीं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत अब काफी हद तक खत्म होती नजर आ रही है. पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते पैदा हुई सप्लाई संकट की स्थिति में अब सुधार आया है, जिससे घरेलू बाजार में राहत देखने को मिल रही है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोलियम कंपनियां अब बुकिंग से ज्यादा सिलेंडर की सप्लाई करने में सफल रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल की शुरुआत में जहां एलपीजी की दैनिक बुकिंग करीब 9 मिलियन तक पहुंच गई थी, वहीं 14 अप्रैल तक यह घटकर 4.3 मिलियन रह गई. यह गिरावट इस बात का संकेत है कि बाजार में पैनिक बुकिंग अब कम हो रही है और उपभोक्ताओं का भरोसा लौट रहा है. युद्ध से पहले औसतन 5.5 मिलियन सिलेंडर प्रतिदिन बुक किए जाते थे, जिसके मुकाबले मौजूदा स्थिति सामान्य के करीब मानी जा रही है.

आंकड़ों के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने 14 अप्रैल को 4.76 मिलियन एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की, जो बुकिंग से अधिक है. इससे यह साफ होता है कि सप्लाई चेन में सुधार हुआ है और कंपनियां मांग को प्रभावी ढंग से पूरा कर रही हैं.

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, क्योंकि देश अपनी लगभग 90 प्रतिशत जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. इस संकट से निपटने के लिए भारत ने वैकल्पिक स्त्रोतों की ओर रुख किया और अमेरिका, अंगोला और ईरान जैसे देशों से एलपीजी आयात बढ़ाया.

एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क से सप्लाई क्रांति

देश में रसोई गैस की सप्लाई व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने करीब 12,500 करोड़ की लागत से एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क मार्ग से होने वाली एलपीजी ढुलाई को कम करना और एक स्थायी, सुरक्षित तथा तकनीकी रूप से उन्नत परिवहन प्रणाली विकसित करना है.

रुपया 19 पैसे मजबूत

मुंबई, 17 अप्रैल अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया गुरुवार को 19 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 93.1475 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 1.25 पैसे की बढ़त में 93.3375 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी.

रुपये की शुरुआत आज 4.75 पैसे ऊपर 93.29 रुपये प्रति डॉलर पर हुई. यह नीचे 93.3575 रुपये प्रति डॉलर तक उतरने के बाद 93.10 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. अंत में 93.1475 रुपये प्रति डॉलर पर रहा.

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने आज भारतीय पूंजी बाजार में 25 करोड़ डॉलर लगाये. इससे रुपये को मजबूती मिली. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रही तेजी ने भारतीय मुद्रा की बढ़त को सीमित रखा.

टैक्स फ्री आय पर भी रिटर्न जरूरी

बड़े खर्च पर आयकर की नजर

स्थायी खाता संख्या से ट्रैकिंग

नई दिल्ली, 17 अप्रैल अगर आपकी आय टैक्स फ्री सीमा के भीतर आती है, तब भी कुछ खास परिस्थितियों में आयकर रिटर्न भरना जरूरी हो सकता है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार केवल कम आय होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपके खर्च और वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में आते हैं. पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख और नई कर व्यवस्था में रु. 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री मानी जाती है.

सामान्य स्थिति में इतनी आय होने पर आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती. लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में आय शून्य होने पर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है. आयकर विभाग का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खर्च उसकी घोषित आय से अधिक दिखाई देते हैं, तो यह संकेत माना जाता है कि उसके पास आय के अन्य स्त्रोत हो सकते हैं, जिन्हें उसने घोषित नहीं किया है. ऐसे मामलों में विभाग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस भेज सकता है. आज के समय में स्थायी खाता संख्या और आधार कार्ड के लिंक होने के कारण हर बड़े वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखना आसान हो गया है. बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड, निवेश और बड़ी खरीदारी की जानकारी सीधे विभाग के सिस्टम में दर्ज हो जाती है.

कई लोग यह सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भरते कि उनकी आय टैक्स फ्री है, लेकिन यह गलती बाद में परेशानी का कारण बन सकती है . महंगी खरीदारी, विदेश यात्रा या बड़े बैंक लेन-देन जैसी गतिविधियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं .इसलिए कर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आपकी वित्तीय गतिविधियां सामान्य से अधिक हैं, तो समय पर आयकर रिटर्न जरूर दाखिल करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी समस्या या नोटिस से बचा जा सके .

इजरायल-लेबनान सीजफायर के कारण तेल हुआ सस्ता

नई दिल्ली, 17 अप्रैल पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राहत का माहौल देखने को मिला, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 2 प्रतिशत तक फिसल गई. निवेशकों की चिंता घटने और सप्लाई में बाधा की आशंका कम होने से बाजार में नरमी आई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा शुरुआती कारोबार में 97.99 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया, जो दिन का निचला स्तर रहा. इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. वहीं ड्ढङ्ग्रढ्ढ क्रूड भी लगभग 2 प्रतिशत टूटकर 92.91 डॉलर प्रति बैरल के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया. यह गिरावट ऐसे समय आई है जब पिछले कारोबारी सत्र में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था.

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड लगभग 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 99.39 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 2 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 93.32 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में यह उतार-चढ़ाव भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता हैघरेलू स्तर पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (स्रूष्टङ्ग) पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे भाव 8,625 रुपये प्रति बैरल तक आ गया.

वैश्विक शेयर बाजारों पर भी इस घटनाक्रम का असर देखने को मिला. एशियाई बाजारों में कमजोरी रही और प्रमुख सूचकांक 1 प्रतिशत तक गिर गए. वहीं वॉल स्ट्रीट में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जहां नैस्डैक और एसएंडपी 500 सूचकांक मामूली तेजी के साथ बंद हुए. भू-राजनीतिक तनाव में कमी की उम्मीद ने तेल बाजार को राहत दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आगे की दिशा पूरी तरह क्षेत्रीय घटनाओं और कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करेगी.

मुद्रा भंडार फिर 700 अरब डॉलर के पार

मुंबई, 17 अप्रैल. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 3.825 अरब डॉलर बढ़कर 700.946 अरब डॉलर पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा का देश का भंडार चार सप्ताह बाद एक बार फिर 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा है. इससे पहले 03 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह 9.063 अरब डॉलर बढ़कर 697.121 अरब डॉलर पर रहा था. रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का योगदान 3.127 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 555.983 अरब डॉलर हो गया. इसमें अमेरिका डॉलर के अलावा जापानी येन, ब्रितानी पाउंड और यूरो भी शामिल हैं जिनका मूल्य निर्धारण डॉलर की तुलना में उनके विनिमय दर के आधार पर किया जाता है.

नए लेबर कोड में ग्रेच्युटी बढ़ेगी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल नई लेबर कोड व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को रिटायरमेंट के समय अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा. हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें और नए नियम भी जोड़े गए हैं, जिनके चलते लाभ और कराधान दोनों पर असर पड़ सकता है.

सरकारी प्रस्तावों के अनुसार, नए श्रम कानून लागू होने के बाद ग्रेच्युटी की गणना और पात्रता के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. कई मामलों में कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक ग्रेच्युटी राशि मिलने की संभावना है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय तक किसी कंपनी या संस्थान में कार्यरत रहते हैं. हालांकि, नए नियमों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ग्रेच्युटी पर कर (टैक्स) से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है.

इससे कुछ कर्मचारियों की नेट इनहैंड राशि पर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जहां एक ओर ग्रेच्युटी की राशि बढ़ने से लाभ दिखाई देता है, वहीं टैक्स नियमों के कारण वास्तविक फायदा कुछ मामलों में सीमित हो सकता है. लेबर कोड का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल और एकीकृत करना है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी लाभ प्रणाली मिल सके.

इसके तहत वेतन संरचना, कार्य समय और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.

भारतीय शेयर बाजारों में आई तेजी

504 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स

156 अंक की बढ़त पर रहा निफ्टी

मुंबई, 17 अप्रैल घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को चौतरफा लिवाली देखी गयी जिससे प्रमुख सूचकांक छह सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 504.86 अंक (0.65 प्रतिशत) चढ़कर 78,493.54 अंक पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 156.80 अंक यानी 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति पर 24,353.55 अंक पर रहा. यह दोनों सूचकांकों का छह सप्ताह का उच्चतम स्तर है.

छोटी और मझौली कंपनियों में जबरदस्त लिवाली रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.25 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.27 प्रतिशत ऊपर बंद हुए.

आईटी की 0.02 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में लिवाली हावी रही. एफएमसीजी का सूचकांक 2.65 प्रतिशत चढ़ गया. टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, धातु, मीडिया, तेल एवं गैस और रियलटी समूहों में भी अच्छी तेजी रही.

सेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर में पौने पांच प्रतिशत का उछाल रहा. पावरग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीईएल, टेक महिंद्रा, टाइटन, अडानी पोर्ट्स, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी के शेयर एक से दो प्रतिशत के बीच चढ़े.एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल के शेयर भी हरे निशान में रहे. सनफार्मा का शेयर एक प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया. महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एलएंडटी में भी गिरावट रही.

सोना-चांदी में आई भारी गिरावट

नई दिल्ली, 17 अप्रैल वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और बाजार में मुनाफावसूली के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,451 रुपए टूटकर करीब 1.52 लाख रुपए पर आ गया है. इससे पहले इसका भाव 1.53 लाख रुपए के आसपास था.

इसी तरह चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट देखी गई है. एक किलो चांदी 1,352 रुपए गिरकर 2.50 लाख रुपए पर पहुंच गई है, जबकि एक दिन पहले यह 2.51 लाख रुपए के स्तर पर थी. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पिछले कुछ दिनों में कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव तेज हो गया है, जिसके चलते निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है और मुनाफावसूली का दौर जारी है.

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 49 दिनों में सोने की कीमतों में कुल 7,442 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी में करीब 16,760 रुपए की कमी आई है. 27 फरवरी को जहां सोना 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं अब यह घटकर 1.52 लाख रुपए के आसपास आ गया है. इसी अवधि में चांदी भी 2.67 लाख रुपए प्रति किलो से फिसलकर 2.50 लाख रुपए तक पहुंच गई है.

चावल, गेहूं के दाम गिरे खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल. घरेलू थोक जिंस बाजारों में शुक्रवार को चावल का औसत भाव गिर गया. चावल के साथ गेहूं भी सस्ता हुआ. चीनी में टिकाव देखा गया जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत छह रुपये घटकर 3,850 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं भी तीन रुपये सस्ता हुआ और 2,781 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे की कीमत गत दिवस के स्तर पर टिकी रही.

मार्क जकरबर्ग बना रहे अपना एआई हमशक्ल

नई दिल्ली, 17 अप्रैल दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में तकनीक और कॉर्पोरेट दुनिया की कार्यशैली को पूरी तरह बदल सकता है.

जकरबर्ग अपना एक फोटोरियलिस्टिक 3डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमशक्ल तैयार करवा रहे हैं, जो न केवल उनकी तरह दिखेगा बल्कि उनकी तरह बातचीत भी कर सकेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह डिजिटल एआई क्लोन कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स में भाग ले सकेगा और उनकी जगह संवाद कर पाएगा. इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यह जकरबर्ग के हाव-भाव, आवाज, बोलने के अंदाज और सोचने के तरीके की नकल कर सके.

कैरों की पट्टी की राजनीति में सक्रियता से हलचल

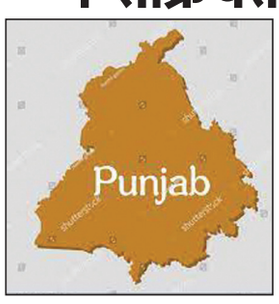

तरनतारन. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व किसानों के भीष्मपितामाह कहलाए जाते प्रताप सिंह केरों की तीसरी पीढ़ी के तौर पर आदेश प्रताप सिंह केरों वर्ष 1997 से पट्टी की सरगर्म राजनीति का हिस्सा हैं. विधानसभा के लगातार चार चुनाव जीतकर गठबंधन की सरकार में तीन बार केबिनेट मंत्री बने केरों इन दिनों पट्टी क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां चलाने लगे हैं.

पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के जेल जाने के बाद केरों का सरगर्म होना कई सियासी पार्टियों लिए चिंता का कारण बन रहा है. हालांकि अकाली दल को केरों के कदवार वाला अभी तक कोई नेता नहीं मिल पा रहा.

1997 में कांग्रेस को छोड़कर आदेश प्रताप सिंह केरों ने शिअद का दामन थामा था. विधायक का चुनाव जीतते ही वह गठबंधन की सरकार में कर आबकारी मंत्री बने. 2002 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन केरों जीतने में कामयाब रहे. 2007 में तीसरी बार जीत दर्ज करवाकर वह खाद्य आपूर्ति मंत्री बने. 2012 में जीत का चौका लगाते दोबारा इसी मंत्रालय पर काबिज हुए. इस बार केरों महज 59 मतों से जीते थे. 2017 में उनको पहली बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि पट्टी से कांग्रेस के हरमिंदर सिंह गिल विधायक बने. 2022 में केरों दूसरी बार चुनाव हारे, क्योंकि आप की तरफ से लालजीत सिंह भुल्लर ने यहां से जीत दर्ज करवाई. विधायक बनते ही वह केबिनेट मंत्री बने. डीएम आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को जेल जाना पड़ा. इधर, भुल्लर जेल पहुंचे तो उधर आदेश प्रताप सिंह केरों ने पट्टी हलके में सियासी एंट्री मारी.

बादल पार्टी में लेने लिए तैयार

केरों की शिअद में वापसी समय अटकलें लगती रहीं, लेकिन ऐसा कुछ सिरे नहीं चढ़ पाया. हैरानी की बात यह है कि केरों जब अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से बैठक करते हैं तो उनके साथ भाजपा नेता गुरमुख सिंह घुल्ला बलेर साथ होते हैं. केरों परिवार की पट्टी में सरगर्मी से अकाली दल को चिंता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हलके में केरों के कदवार वाला कोई और नेता पार्टी के पास नहीं है. अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का हिस्सा बने केरों कोर कमेटी के सदस्य भी हैं. सूत्रों की मानें तो भविष्य में वह किसी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

ममता बनर्जी के साथ क्षेत्रीय दल एकजुट

अखिलेश-तेजस्वी और हेमंत का साथ; भाजपा-कांग्रेस अकेले

रांची. बंगाल विधानसभा चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती नजदीकियां विपक्ष की नई धुरी बनने के संकेत दे रही हैं.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीतिक सक्रियता इस दिशा में अहम मानी जा रही है. तेजस्वी

और अखिलेश के बाद जल्द ही हेमंत सोरेन भी ममता बनर्जी के पक्ष में अभियान आरंभ करने के लिए बंगाल का रुख कर सकते हैं. इन तीनों नेताओं की राजनीति अपने-अपने राज्यों में मजबूत सामाजिक आधार पर टिकी है.

हेमंत सोरेन जहां आदिवासी और क्षेत्रीय मुद्दों को केंद्र में रखते हैं, वहीं तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की राजनीतिक धारा को आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ा-दलित-मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में हैं. अब ये तीनों नेता भाजपा के खिलाफ एक साझा रणनीति के तहत ममता बनर्जी के साथ तालमेल बढ़ाते नजर आ रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात लंबे समय से उठती रही है, लेकिन ठोस नेतृत्व का अभाव हमेशा बाधा रहा. ऐसे में ममता बनर्जी का आक्रामक राजनीतिक रुख और भाजपा के खिलाफ उनकी स्पष्ट रणनीति उन्हें इस संभावित गठबंधन का स्वाभाविक चेहरा बना रही है.

क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर निर्भर नहीं

बंगाल में उनकी पकड़ और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता इस उभरते समीकरण को मजबूती दे सकती है. इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिख रही है. कई राज्यों में संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता ने उसे विपक्षी एकजुटता की धुरी बनने से रोका है. क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्तर पर गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रहे हैं. इससे भविष्य में विपक्षी राजनीति का स्वरूप बदल सकता है.

विशेष | **राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने किया बचाव**

वसुंधरा के बयान से भाजपा में हलचल!

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाज़ी के चलते हलचल तेज हो गई है. दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं और वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के हालिया बयानों ने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

पहले दिए गए उनके बयान मेरी ही सुनवाई नहीं होती और बाद में सफाई में लगाए गए साजिश के आरोप ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वसुंधरा राजे किसी साजिश का शिकार हैं या उनके बयानों में उनका दर्द झलक रहा है. इसी बीच, टोंक दौरे पर आई भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने राजे के बयान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि

वसुंधरा राजे द्वारा सफाई में दिया गया वक्तव्य पूरी तरह सही है और पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा एकजुट संगठन है और वसुंधरा राजे पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते सम्मान की पात्र हैं. डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी में उनका महत्वपूर्ण स्थान है. उनके विचार हमारे लिए अहम हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं.

विपक्ष जमीनी हकीकत समझकर ही प्रतिक्रिया दे

वहीं, वसुंधरा राजे के मैं खुद का नहीं बचा पाई, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं वाले बयान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हर बार जरूरी नहीं कि कोई मुख्यमंत्री बने वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर अलका गुर्जर ने संतुलित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर बेहतर जवाब संबंधित नेता ही दे सकते हैं. कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को जमीनी हकीकत समझकर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

तमिलनाडु में आप की एंट्री

एमके स्टालिन के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली. दक्षिण भारत की राजनीति में इस बार एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) के पक्ष में हुंकार भरेंगे. केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए 20 अप्रैल को चेन्नई पहुंचेंगे. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है.

जानकारी के अनुसार, केजरीवाल का यह दौरा दो दिवसीय होगा. वह 20 और 21 अप्रैल को तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे. 20 अप्रैल को चेन्नई पहुंचने के तुरंत बाद, वह मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ मंच साझा कर सकते हैं. इसके बाद अगले दिन 21 अप्रैल को भी उनकी कई रैलियां और रोड शो प्रस्तावित हैं. हालांकि, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन पार्टी ने सेकुलर प्रोग्रेसिव एलायंस को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है. केजरीवाल का यह दौरा भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ एक साझा मोर्चा खड़ा करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल बनेगा चुनावी मुद्दा-अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में दिल्ली और पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा करेंगे. साथ ही, वह एम. के. स्टालिन सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए मतदाताओं से डीएमके के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे. गौरतलब है कि स्टालिन और केजरीवाल के बीच पहले भी कई मौकों पर आपसी समन्वय देखा गया है, खासकर केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे के मुद्दे पर दोनों नेता एक ही सुर में बात करते रहे हैं.

चुनावी जुगलबंदी डीएमके के लिए कितनी फलदायी

तमिलनाडु की राजनीति में आमतौर पर क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा रहा है, लेकिन केजरीवाल जैसे उत्तर भारतीय नेता का द्रविड़ राजनीति के मंच पर उतरना चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की यह चुनावी जुगलबंदी डीएमके के लिए कितनी फलदायी साबित होती है. केजरीवाल और एम.के. स्टालिन के बीच पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी नजदीकियां देखी गई हैं. दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे पर कई बार मंच साझा किया है.